

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA
CRIMINAL MISCELLANEOUS No.76684 of 2024

Arising Out of PS. Case No.-1619 Year-2023 Thana- SIWAN COMPLAINT CASE District-
Siwan

=====

Aniket Kumar, son of Arun Singh, Director of Harischandra Builder Private Limited, having its office and R/o Maghari, P.S.- Bhagwanpur Hat, District -Siwan Bihar.

... .. Petitioner/s

Versus

1. The State of Bihar.
2. Sanjeev Kumar, Son of Prabhunath Mishra, R/o – Maghari, P.S.- Bhagwanpur Hat, District -Siwan, Bihar.

... .. Opposite Party/s

=====

Appearance :

For the Petitioner/s :	Mr.Rakesh Mohan Singh, Advocate
For the Opposite Party/s :	Mr.Pramod Kumar Pandey, APP
For the O.P. No. 2 :	Mr. Mr. D.K. Sinha, Sr. Advocate
	Mr. Alexander Ashok, Advocate
	Ms. Shyama Rani, Advocate

=====

CORAM: HONOURABLE MR. JUSTICE CHANDRA SHEKHAR JHA
ORAL JUDGMENT

Date : 25-02-2025

1. Heard learned counsel appearing on behalf of the parties.

2. The present application has been filed for quashing the cognizance order dated 12.10.2023 passed by learned Judicial Magistrate 1st Class, Siwan in connection with Complaint Case No. 1619 of 2023, where cognizance was taken for the offence under section 138 of the Negotiable Instruments Act.

3. While arguing this matter, learned counsel heavily relied upon the legal notice from wherein, it transpires that the compliance of Section 138(b) of the Negotiable Instrument Act, 1881 not appears to be followed as demand



was not raised for the **"said amount"** i.e. the amount for which the instrument under dispute was drawn by opposite party no. 2. It is submitted that on this score alone, the entire cognizance order is bad in eyes of law and same be fit to be set aside/quashed. Besides the aforesaid main illegality, it is submitted by learned counsel appearing for the petitioner that there was dispute between the parties related with their business and deed of partnership as executed between them on 15.10.2019 was not complied with in its true spirit. It is also submitted that the instrument in issue was issued by a company i.e. M/s Harishchandra Builders Pvt. Ltd., a company registered under Companies Act, 2013 but said company was not made an accused in this case. Notice appears issued to petitioner in personal capacity. Learned counsel appearing for petitioner relied upon the legal report of Hon'ble Supreme Court as available through ***Upasana Mishra Vs. Trek Technology India Pvt. Ltd.*** reported through ***2023 SCC OnLine SC 1740.***

4. Mr. D.K. Sinha, learned senior counsel appearing for the opposite party no. 2 submitted that the firm of



opposite party no. 2 is a proprietorship firm and, therefore, the notice was issued in personal capacity. It is pointed out that the firm of petitioner is also a proprietorship firm. Mr. Sinha Further submitted that the demand of Rs. 35 lacs was out of total outstanding demand of Rs. 80,20,000/- and it was so raised to protect the interest of opposite party no. 2 in case of summary suit, if any initiated in future regarding recovery of the aforesaid amount.

5. It would be apposite to reproduce the provision of Section 138(b) of the Negotiable Instrument Act, for the sake of better understanding of the position of law.

"138. Dishonour of cheque for insufficiency, etc., of funds in the account.—

"Where any cheque drawn by a person on an account maintained by him with a banker for payment of any amount of money to another person from out of that account for the discharge, in whole or in part, of any debt or other liability, is returned by the bank unpaid, either because of the amount of money standing to the credit of that account is insufficient to honour the cheque or that it exceeds the amount arranged to be paid from that account by an agreement made with that bank, such person shall be deemed to have committed an offence and shall without prejudice to any other provisions of this Act, be punished with imprisonment for 1["a term which may extend to two year"], or with fine which may extend to twice the amount of the cheque, or with both:

Provided that nothing contained in this section shall apply unless-

(a) The cheque has been presented to the bank within a period of six months from the date on which it is drawn or within the period of its validity, whichever is earlier.



(b) The payee or the holder in due course of the cheque, as the case may be, makes a demand for the payment of the said amount of money by giving a notice, in writing, to the drawer, of the cheque, 2["within thirty days"] of the receipt of information by him from the bank regarding the return of the cheques as unpaid"

(C).....

6. To understand the factual position, it would be apposite to reproduce the notice as issued by opposite party no. 2 against petitioner for raising his demand of Rs. 35 lacs, same is as :-

“प्रेषक:- विवेक कुमार

अधिवक्ता

व्यवहार न्यायालय, सिवान (बिहार)

पिन कोड- 841226

द्वारा:- संजीव कुमार

पिता-श्री प्रभुनाथ मिश्रा

ग्राम-मधरी

थाना-भगवानपुर हाट

जिला- सिवान।

प्रेषित:- अनिकेत कुमार

वल्द श्री अरुण सिंह

ग्राम-मधरी

थाना-भगवानपुर हाट

जिला-सिवान

प्रोप्राइटर-हरिश्चन्द्र विल्डर प्राइवेट लिमिटेड

मौजा-मधरी, थाना-भगवानपुर हाट,

जिला-सिवान।

रजिस्ट्रेशन नं०-20AADCH5185K1ZL

डाल्टेनगंज (झारखण्ड)

चुं मेरे उपरोक्त मुवक्किल संजीव कुमार

ने आपको यह वकालतन नोटिश भेजने के

लिए मुझे अधिकृत किया है:-

1. यह कि मेरे मुवक्किल का कहना है कि मेरे मुवक्किल और आपके कम्पनी हरिश्चन्द्र विल्डर प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से कलपत्रु पावर ट्रान्समिशन लिमिटेड डाल्टेनगंज से संयुक्त रूप से बिल्डिंग निर्माण के काम करने के लिए एक लिखित करार वर्ष 2019 में हुआ।

2. यह कि उस करार के अनुसार कलपत्रु पावर ट्रान्समिशन लिमिटेड डाल्टेनगंज के अन्तर्गत होने वाले कामों में जो भी व्यय होगा वह दोनों भागीदार बराबर-बराबर करेंगे और सभी कारोबार हरिश्चन्द्र विल्डर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से होगा एवं कलपत्रु पावर ट्रान्समिशन लिमिटेड डाल्टेनगंज से जो भुगतान होगा वह हरिश्चन्द्र विल्डर प्राइवेट लिमिटेड के खाते में ही आयेगा जिसमें दोनों भागीदार का बराबर का अधिकार होगा।



3. यह कि मेरे मुवक्किल का कहना है कि कलपत्रु पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड द्वारा राजहरा स्टेशन बिल्डिंग एवं ई-केविन का काम शुरू हुआ और 2021 में सम्पन्न हो गया। जिसका भुगतान कलपत्रु पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड ने स्टेशन बिल्डिंग का विभिन्न तिथियों में कुल 11761136.2 (एक करोड़ सतरह लाख एकसठ हजार एक सौ छतीस रुपया दो पैसा) एवं ई-केविन का भुगतान विभिन्न तिथियों में कुल 5236188.21 (बावन लाख छतीस हजार एक सौ अठासी रुपया इक्कीस पैसा) यानी कुल भुगतान 16997324.41 (एक करोड़ उनहतर लाख सनतानवे हजार तीन सौ चौबीस रुपया एकतालीस पैसा) हरीशचन्द्र बिल्डर प्राईवेट लिमिटेड के खाते में किया।
4. यह कि मेरे मुवक्किल का कहना है कि कलपत्रु पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड ने जब-जब आपके कम्पनी हरीशचन्द्र बिल्डर प्राईवेट लिमिटेड के नाम पर भुगतान किया तब मेरे मुवक्किल से हिसाब करने को कहा तब आप यह कह कर की अभी काम बाकी है काम पुरा हो जायेगा तब हिसाब होगा टाल दिया करते थे।
5. यह कि मेरे मुवक्किल ने काम खत्म हो जाने के बाद आपसे हिसाब करने की बात कही तो आप आज-कल कर टाल देते थे। इस बात पर मेरे मुक्किल को बहुत हैरानी होती थी। इस बात को जब मेरे मुवक्किल ने अपने घर वालों एवं गांव के लोगों से कहा तब लोगों के कहने पर आपने भागीदारी में किए कार्य का हिसाब-किताब किया जिसमें से मेरे मुवक्किल का उस दिन तक का हिसाब 8020000/- (अस्सी लाख बीस हजार रुपया) का हिसाब आया जो आपको मेरे मुवक्किल को देने थे।
6. यह कि मेरे मुवक्किल का कहना है कि आपने यह कह कर की अभी पैसा नहीं है मैंने वह पैसा कही और लगा दिया है बाद में देंगे और पैसा देने के लिए समय मांगते रहे। मेरा मुवक्किल भी आपकी बातों एवं झांसा में आकर आपको समय देता गया।
7. यह कि जब मेरे मुवक्किल को पैसा की अत्यंत जरूरत पड़ी तो वह कुछ लोगों को लेकर आपके पास गया और आपसे अनुरोध किया की मुझे मेरे हिस्से का पैसा दे दीजिए मुझे जरूरत है। तब आपने कुल तीन किस्तों में कुल रकम को देने को स्वीकार किया तथा पहला किस्त-3500000/- (पैंतीस लाख रुपया) को चेक आपने मेरे मुवक्किल का दिया और बाकी किस्त देने के लिए एक समय लिया। मेरे मुवक्किल ने आपके बातों को विश्वास कर आपको फिर समय दिया और आपके द्वारा दिया गया चेक दिनांक-11.05.2023 को अपने HDFC बैंक खाते में जमा किया।
8. यह कि मेरे मुवक्किल का कहना है कि 12.05.2023 को HDFC बैंक के द्वारा उसको सुचना मिली की उसके द्वारा डाला गया चेक फंड की कमी (Funds Insufficient) के कारण अमान्य हो गया।
9. यह कि मेरे मुवक्किल ने इसकी सुचना आपको दिया तो आपने फिर से वहीं चेक 3500000/- (पैंतीस लाख रुपया) का डालने को बोला और बोला कि अब मेरे खाते में पैसा है अब आप निकाल सकते हैं। मेरे मुवक्किल ने आपके द्वारा दिया हुआ दिनांक-26.06.2023 का चेक अपने HDFC के खाते में डाला और वह भी 27.06.2023 को HDFC बैंक के द्वारा फंड की कमी (Funds Insufficient) कह कर अमान्य कर दिया गया।
10. यह कि मेरे मुवक्किल का कहना है कि अब आप ना



ही मिलते हैं और ना ही आजतक उसके हिस्सा का पैसा नहीं दिए और जानबुझकर गलत चेक देकर रकम हड़प लिए हैं।

11. यह कि मेरे मुवक्किल का कहना है कि आपके व्यवहार से ऐसा प्रतीत होता है कि आप उसका कुल रकम मो0 8020000/- (अस्सी लाख बीस हजार) रुपया हड़प जाना चाहते हैं जो सरासर धोखाधड़ी एवं अमानत में ख्यानत है और आपके कम्पनी के साथ हुए करार एवं शर्तों के विपरीत भी है।

अतः बजरिये इस वकालतन नोटिस आपको आगाह किया जाता है कि आप इस नोटिस के 15 दिनों के अन्दर मेरे मुवक्किल की कुल रकम मो0- 8020000/- (अस्सी लाख बीस हजार रुपया) का सुद सहित एक मुस्त भुगतान कर देवे अन्यथा बाध्य होकर मेरे मुवक्किल को न्याय हेतु न्यायालय की शरण में जाना पड़ेगा जिससे समस्त खर्च की जवाबदेही आपकी होगी। इसे सख्त ताकीद समझे।

इस वकालतन नोटिस की एक प्रति साथ वकालतनामा एवं समस्त कागजात मेरे कार्यालय में अग्रिम कार्यवाही हेतु सुरक्षित रखा जाता है।

भवदीय

ह0/-

विवेक कुमार

अधिवक्ता

व्यवहार न्यायालय

सिवान।”

7. It would be further apposite to reproduce the para nos. 7 and 8 of the ***Upasana Mishra’ case (supra)***.

“7. The last paragraph in Annexure-P2 notice carries the demand and we will refer to the demand made thereunder. It read, thus:

“9.

..... I, therefore through this legal notice call upon you to make the party of the doubt amount of the cheque i.e. Rs. 6,50,000/- (Rs. Six Lakh Fifty Thousand Only) with interest @12% per annum since 12.11.2013 and further pay the damaged at Rs. 50,000/- (Rs. Fifty Thousand Only) per month within stipulated period from the receipt of this notice failing which I have clear instructions from my aforesaid clients to take legal action against you in the competent courts, holding you responsible for entire cost and consequences with litigation charges of Rs. 5,500/- (Rs. Five Thousand Five Hundred Only) as charges of this notice. Copy of this kept for further reference.” (Emphasis added)

8. A scanning of Annexure-P2 notice would reveal that an omnibus demand for Rs.



6,50,000/- was made in addition to the demand for interest @12 per annum since 12.11.2013, the date of returning of the cheque, Rs. 50,000/- towards damages and Rs. 5,500/- as notice charge. The demand is omnibus as relates the amount of Rs. 6,50,000/- as admittedly, it is not the cheque amount and in addition under Annexure P-2-notice, interest @12% per annum from 12.11.2013, damages at Rs. 50,000/- per month and Rs. 5,500/- as notice charge were also demanded. Such circumstances discernible from the demand notice on application of the law laid by this Court in the case of Suman Sethi (supra), would make Annexure-P2 notice of demand invalid. Hence, we are of the view that the impugned order invites interference. In that view of the matter, the Appeal stands allowed. Consequently, the impugned order dated 13.04.2023 passed by the High Court of Delhi at New Delhi in CRMC No. 2528/2023 stands set aside and as a necessary sequel, the summoning order dated 19.01.2016 passed by the learned Metropolitan Magistrate, NI Act 02, South East, Saket Courts, New Delhi shall also stand quashed.”

8. It appears from the notice dated 26.07.2023, as issued by opposite party no. 2, against petitioner that it nowhere suggest that any demand *qua* Rs. 35 lacs, which is the amount of dishonoured instrument as drawn on Bank of Baroda dated 11.05.2023 bearing no. 00154 was raised. Notice is even silent regarding any description of instrument which is the subject matter of present proceedings.

9. From the bare perusal of para-11 of the notice (running from page 32 to 35), it transpires that the demand was raised for Rs. 80, 20,000/- with interest, which is not the



“said amount” in terms of Section 138(b) of the Negotiable Instrument Act as discussed above. This case further appears fully covered by the ratio as available to this Court thorough ***Upasana Mishra Case (supra)***, accordingly, impugned order of cognizance dated 12.10.2023 passed by learned Judicial Magistrate 1st Class, Siwan in connection with Complaint Case No. 1619 of 2023, is hereby set aside and quashed *qua* petitioner with all its consequential proceedings.

10. Let copy of this order be sent to the trial court, without delay.

(Chandra Shekhar Jha, J)

veena/-

AFR/NAFR	AFR
CAV DATE	NA
Uploading Date	27.02.2025
Transmission Date	27.02.2025

